

ट्रेड डील से रिश्तों को मिलेगी नई मजबूती

'मेड इन इंडिया' को राहत, बढ़ेगा कारोबार

▶ भारत-अमेरिका ट्रेड डील से उद्योग जगत में खुशी की लहर

नई दिल्ली, 03 फरवरी. भारत-अमेरिका के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापार समझौते ने देश के उद्योग जगत में नई उम्मीद जगा दी है। भारतीय उत्पादों पर अमेरिका में टैरिफ घटाकर 18 प्रतिशत किए जाने के फैसले को उद्योगपतियों ने दूरदर्शी कदम बताया है।

महिंद्रा, बिड़ला ग्रुप और एनएसई समेत कई दिग्गज कारोबारी नेताओं ने कहा कि यह समझौता न सिर्फ व्यापार, बल्कि रणनीतिक साझेदारी को भी नई मजबूती देगा। भारत और अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते पर देश के प्रमुख उद्योगपतियों ने खुलकर खुशी जताई है। नेशनल

स्टॉक एक्सचेंज के एमडी और सीईओ आशीष कुमार चौहान ने इस डील को कारोबार, सप्लाय चैन और भारत-अमेरिका साझेदारी के लिए 'बड़ी जीत' बताया। वहीं महिंद्रा ग्रुप सीईओ डॉ. अनिश शाह ने कहा कि पारस्परिक शुल्क में कटौती और गैर-शुल्क बाधाओं को कम करने की प्रतिबद्धता से निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि अब 'मेड इन इंडिया' उत्पादों पर अमेरिका में केवल 18 प्रतिशत टैरिफ लगेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की पुष्टि करते हुए इसे दोनों देशों के लिए फायदेमंद बताया है। भारत और अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते को लेकर अमेरिकी प्रशासन में सकारात्मक प्रतिक्रिया सामने आई है।

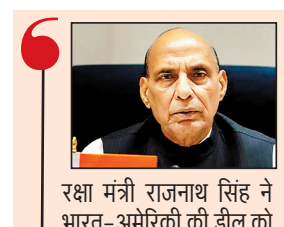
अमेरिका के कृषि मंत्री क्रक रोलिंस और ऊर्जा मंत्री इग बर्गम ने भारत के साथ हुए व्यापार समझौते का स्वागत करते हुए इसके व्यापक लाभों को रेखांकित किया है। कृषि मंत्री रोलिंस ने कहा कि यह समझौता भारत जैसे बड़े और तेजी से बढ़ते बाजार में अमेरिकी कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देगा। उन्होंने बताया कि 2024 में भारत के साथ अमेरिका का कृषि व्यापार घाटा लगभग 1.3 बिलियन डॉलर था और यह समझौता उस घाटे को कम करने में मददगार साबित होगा। रोलिंस ने इसे अमेरिका फर्स्ट की जीत करार दिया।

नई दिल्ली, 3 फरवरी. भारत और अमेरिका के बीच हुए बहुप्रतीक्षित ट्रेड डील को सरकार की आधिकारिक मंजूरी मिल गई। इस समझौते को दोनों देशों के रिश्तों में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।

कई वरिष्ठ नेताओं ने इस डील का स्वागत करते हुए इसे रोजगार, विकास और तकनीकी सहयोग के लिए मील का पत्थर बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बातचीत के बाद भारत-अमेरिका ट्रेड डील को नई दिशा मिली है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत के



बाद द्विपक्षीय व्यापार पर हुई घोषणाओं का स्वागत है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों में रोजगार सृजन, आर्थिक विकास और इन्वैशमेंट को बढ़ावा देगा। उन्होंने इसे 'मेक इन इंडिया' और भरोसेमंद टेक्नोलॉजी साझेदारी को मजबूत करने वाला कदम बताया। यह डील किसानों, एमएसएमई, उद्यमियों और कुशल श्रमिकों के लिए अभूतपूर्व अवसर है।



रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत-अमेरिका की डील को गहरे और बड़े आर्थिक सहयोग का एक नया अध्याय बताया। उन्होंने लिखा, भारत-अमेरिका संबंधों के लिए यह एक ऐतिहासिक पल है, क्योंकि एक ऐतिहासिक व्यापार समझौता फाइनल हो गया है। इससे टैरिफ काफी कम होकर 18 प्रतिशत हो गए हैं, जिससे गहरे और बड़े आर्थिक सहयोग का एक नया अध्याय शुरू हुआ है।



केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लिखा- मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का उनके दूरदर्शी और निर्णायक नेतृत्व व भारत-अमेरिका संबंधों को मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए आभारी हूँ। यह एक जैसी सोच वाले, निष्पक्ष व्यापार करने वाले दो लोकतंत्रों की साझा समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की ताकत को दिखाता है।



रेलवे, सूचना और प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा- अमेरिका और भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। दोनों देश स्वाभाविक सहयोगी हैं। साथ मिलकर भारत और अमेरिका के पास शांति और विकास के लिए काम करने की अपार क्षमता है। अमेरिका और भारत की ताकतें एक-दूसरे की पूरक हैं। दोनों देश मिलकर ऐसी टेक्नोलॉजी बना सकते हैं।

भारत ने प्रतिमा गायब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की

नई दिल्ली. भारत ने ऑस्ट्रेलिया में महात्मा गांधी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने तथा गायब करने की घटना की निंदा करते हुए इसके दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में मीडिया के सवालियों के जवाब में मंगलवार को कहा कि भारत ने इस मुद्दे को ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों के समक्ष सख्तों के साथ उठाया है। हम मेलबर्न के रोविविल स्थित ऑस्ट्रेलियन इंडियन कम्युनिटी सेंटर में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा क्षतिग्रस्त किए जाने और हटाए जाने की कड़ी निंदा करते हैं।

हेट स्पीच मामले में सुको में हुई सुनवाई

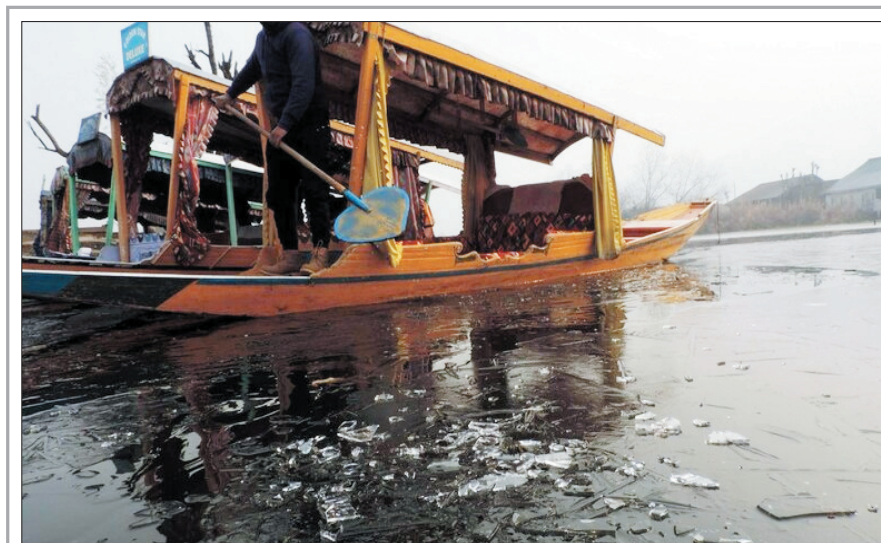
नई दिल्ली, 03 फरवरी. उच्चतम न्यायालय ने नोएडा हेट स्पीच मामले में पुलिस की निष्क्रियता का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई की।

इस याचिका को एक मुस्लिम धर्मगुरु ने दायर किया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि हेट स्पीच मामले में स्थानीय पुलिस में बार-बार शिकायत करने के बावजूद उसने मामला दर्ज करने से इनकार किया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने घटना की निष्पक्ष एवं तटस्थ जांच की मांग करने वाली याचिका एवं शिकायत पर कार्रवाई करने में कथित रूप से विफल रहे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर भी विचार किया। शीर्ष अदालत ने हाल ही में हेट स्पीच से



संबंधित याचिकाओं में अपना आदेश सुरक्षित रखा है लेकिन उसने इस मामले को लंबित रखने का निर्णय लिया क्योंकि इसमें अलग मुद्दे उठाए हैं। मामले में केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने कहा यह मामला पहले से चल रहा है इसलिए इसकी बहुत हद तक प्रासंगिकता नहीं है और याचिका में अब कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं बचा है।

न्यायमूर्ति मेहता ने उल्लेख किया कि कुछ अपराधों के लिए अभियोजन को बिना अधिकारिक अनुमोदन के नहीं बढ़ाया जा सकता है। अहमदी ने विरोधी दर्ज करते हुए कहा कि इस चरण में किसी अनुमोदन का सवाल नहीं है और तर्क दिया कि हेट स्पीच के लिए एफआईआर दर्ज करने में बार-बार विफल रहना एक प्रणालीगत समस्या की ओर इशारा करता है जिसका राष्ट्रीय अखंडता पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। पीठ ने मामले का सामाजिककरण करने के खिलाफ चेतावनी दी क्योंकि अदालत विशेष घटना पर सुनवाई कर रही थी।



कश्मीर की जमी डल झील, माइनस में पहुंचा तापमान

जम्मू. जम्मू-कश्मीर की मशहूर डल झील के कुछ हिस्से और कश्मीर में कई पानी की जगहें जम गईं, जिससे पूरी घाटी में तापमान और गिर गया। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान माइनस 5.2 डिग्री दर्ज किया गया है।

संसद में सरकार मुझे बोलने नहीं देती

▶ राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखा पत्र

नई दिल्ली, 03 फरवरी. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को मंगलवार को पत्र लिखकर कहा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लेने के दौरान उन्हें बोलने से रोका जाना चिंता का विषय है और यह लोकतंत्र की परंपरा के लिये गहरा आघात है।

राहुल गांधी ने अपने पत्र में कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सोमवार को जिस तथ्य को प्रमाणित करने के बहाने उन्हें बोलने से रोका गया है उसकी प्रमाणिकता के संदर्भ में उन्होंने

श्री गांधी ने आगे लिखा आज मुझे लोकसभा में बोलने से रोका जाना न केवल इस परंपरा का उल्लंघन है, बल्कि यह एक गंभीर चिंता भी पैदा करता है कि विपक्ष के नेता के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों पर मुझे जानबूझकर बोलने से रोका जा रहा है। यह दोहराना उचित होगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्रपति के अभिभाषण का एक प्रमुख हिस्सा थी, जिस पर संसद में चर्चा आवश्यक है। उन्होंने लिखा आपकी संवैधानिक और संसदीय जिम्मेदारी है कि आप प्रत्येक सदस्य के अधिकारों की, विशेषकर विपक्षी सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करें।

सदन के पटल पर दस्तावेज पेश कर दिया है। उन्होंने लिखा आपने जिस दस्तावेज को प्रमाणित करने का निर्देश दिया था आज मैंने अपनी बातचीत को पुनः शुरू करते हुए उस को प्रमाणित कर दिया। सदन की लंबी परंपरा में पूर्ववर्ती अध्यक्षों के ऐसे मामलों में समय समय पर दिए गये निर्णय भी शामिल हैं। सदन में किसी दस्तावेज का उल्लेख करने



वाला सदस्य प्रस्तुत तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए बाध्य होता है और इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद अध्यक्ष उस सदस्य को दस्तावेज का उद्धरण देने या उसका उल्लेख करने की अनुमति देते हैं। इसके बाद उस दस्तावेज पर प्रतिक्रिया देने का काम सरकार का हो जाता है और अध्यक्ष की भूमिका समाप्त हो जाती है।

वांगचुक लोगों को भड़काने के आरोप में हिरासत में है : केंद्र

नई दिल्ली. 03 जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत उनकी हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।

केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि वांगचुक को पाकिस्तान और चीन से संदे एक सीमावर्ती एवं संवेदनशील क्षेत्र में लोगों को भड़काने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले में सभी प्रक्रियागत सुरक्षा उपायों का पूरी तरह पालन किया गया है।

न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति पी.बी. वराले की पीठ के समक्ष केंद्र ने दलील दी कि यह क्षेत्र रणनीतिक रूप से अत्यंत संवेदनशील है और वहां किसी भी तरह का उकसाव राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अदालत ऐसे व्यक्ति से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही है, जो सीमावर्ती इलाके में जनभावनाओं को भड़काने का प्रयास कर रहा था। वहीं, सोनम वांगचुक की पत्नी गीताजलि जे. अंगमो की ओर से दायर याचिका में हिरासत को अवैध बताते हुए मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।

बजट से राजस्थान के विकास को मजबूती

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय बजट को लेकर कहा

जयपुर, 03 फरवरी. राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से पेश किया गया आम बजट 2026-27 राजस्थान की प्रगति और विकास को मजबूती देगा।

श्री शर्मा मंगलवार को राजस्थान विधानसभा में सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने से पहले यहां पक्ष लॉबी में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक दल की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक के प्रारंभ में ही पूर्व मंत्री हेम सिंह भडाना एवं पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल के निधन पर दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों एवं विधायकों



को सदन में अच्छी उपस्थिति के लिए प्रेरित किया तथा कहा कि इस सत्र की कार्यवाही का आमजन के हितों के लिए पूरा सदुपयोग किया जाए। उन्होंने सदन में अच्छे बोलने वाले विधायकों की सराहना भी की। उन्होंने कहा केंद्र सरकार की ओर से पेश किया गया आम बजट राजस्थान की प्रगति और विकास को मजबूती देगा और इसमें पर्यटन, उद्योग, आईटी, एआई जैसे क्षेत्रों में किए गए प्रावधानों से राजस्थान में इन क्षेत्रों में विकास होगा।

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को यहां राधा स्वामी सत्संग (व्यास) के संरक्षक जसदीप सिंह गिल से मुलाकात की। उन्होंने आम बजट में राजस्थान के लिए रेलवे क्षेत्र में किए गए 10 हजार करोड़ रुपये के बजट प्रावधान का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता है। सरकार की योजनाओं के माध्यम से पिछले दो वर्षों में जमीनी स्तर पर योजनाओं का सफल क्रियान्वयन कर इसे सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने राज्य में चल रहे ग्राम उद्यान शिविरों का लाभ उठाने की अपील की।

डीआरडीओ ने सॉलिड फ्यूल डक्टेटेड रैमजेट तकनीक का किया परीक्षण

नई दिल्ली, 03 फरवरी. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने मंगलवार को सॉलिड फ्यूल डक्टेटेड रैमजेट तकनीक का सफल फ्लाइंग टेस्ट किया। इस सफलता के साथ भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है, जिनके पास यह आधुनिक तकनीक है।

रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह टेस्ट ओडिशा के तट के पास चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज (आईटीआर) में किया। यह तकनीक लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों बनाने में मदद करती है। इस तकनीक से संभावित विरोधियों के मुकाबले रणनीतिक बढ़त मिलती है। परीक्षण के दौरान

सभी प्रमुख उप-प्रणालियों ने अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन किया। इनमें बिना नोजल वाला बूस्टर, सॉलिड फ्यूल डक्टेटेड रैमजेट मोटर और फ्यूल फ्लो कंट्रोलर शामिल थे। सिस्टम को पहले प्राइंड बूस्टर मोटर की मदद से निर्धारित मैक संख्या तक पहुंचाया गया, जिसके बाद एसएफडीआर प्रणाली ने सफलतापूर्वक काम किया। पूरे परीक्षण की निगरानी और पुष्टि आईटीआर, चांदीपुर की ओर से बंगाल की खाड़ी के तट पर तैनात कई ट्रैकिंग उपकरणों से प्राप्त डेटा आंकड़ों के जरिए की गई। टेस्ट के दौरान डीआरडीओ की विभिन्न प्रयोगशालाओं के वरिष्ठ वैज्ञानिक मौजूद रहे।

लंबी दूरी की मिसाइल का सफल परीक्षण

नई दिल्ली 03 फरवरी. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने लंबी दूरी की मिसाइलों के विकास में सहायक सॉलिड फ्यूल डक्टेटेड रैमजेट प्रौद्योगिकी का मंगलवार को ओडिशा की चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज (आईटीआर) से सफल परीक्षण किया।

रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस सफल परीक्षण के साथ भारत उन चुनिंदा देशों के विशिष्ट समूह में शामिल हो गया है जिनके पास यह अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी है। यह प्रौद्योगिकी हवा-से-हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइलों के विकास में सहायक है और प्रतिद्वंद्वियों पर सामरिक बढ़त प्रदान करती है। परीक्षण के दौरान सभी उप-प्रणालियों—



जिनमें नोजल-रहित बूस्टर, सॉलिड फ्यूल डक्टेटेड रैमजेट इंजन तथा ईंधन प्रवाह नियंत्रक शामिल हैं ने अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन किया। प्रणाली के प्रदर्शन की पुष्टि उड़ान के दौरान एकत्र किए गए आंकड़ों से हुई, जिन्हें बंगाल की खाड़ी के तट पर

चांदीपुर स्थित आईटीआर द्वारा तैनात विभिन्न ट्रैकिंग उपकरणों ने दर्ज किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. समीर वी. कामत ने सफल परीक्षण के लिए डीआरडीओ और उद्योग जगत को बधाई दी।

आज का इतिहास

- 1687- ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में नगर निगम बनाया था।
- 1845- पहला आंग्ल सिख युद्ध भड़का।
- 1882- तमिल कवि सुब्रह्मण्यम भारतीय का जन्म हुआ।
- 1911- मिस्र के उन्प्यासकार नजीब महफूज का जन्म, वह साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले अरबी लेखक बन।
- 1935- पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का जन्म।
- 1936- अमेरिका की एक तलाकशुदा महिला से विवाह की इच्छा पूरी नहीं होने पर ब्रिटेन के किंग एडवर्ड अष्टम ने स्वेच्छा से तख्तों-ताज छोड़ दिया।

दिल्लीवासियों को होली-दिवाली पर मुफ्त मिलेगा एलपीजी सिलेंडर

नई दिल्ली, 03 फरवरी. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली के सभी राशनकार्ड धारकों को होली और दिवाली पर निशुल्क गैस सिलेंडर दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने उस योजना को मंजूरी दे दी है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2026 से दिल्ली के सभी राशन कार्ड धारक परिवारों को प्रतिवर्ष दो एलपीजी सिलेंडर के बराबर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता होली और दिवाली जैसे प्रमुख त्योहारों के अवसर पर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि यह योजना दिल्ली सरकार की लक्षित, पारदर्शी और जवाबदेह कल्याण



नीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि सिलेंडर की निर्धारित राशि डीबीटी के माध्यम से परिवार के मुखिया के आधार-सीडेड बैंक खाते में प्रदान की जाएगी। इस योजना पर होने वाला अनुमानित वार्षिक व्यय लगभग 242.77 करोड़ रुपये होगा, जो एलपीजी कीमतों, भारत सरकार की सब्सिडी तथा लाभार्थियों की संख्या में परिवर्तन के अनुसार समायोजित किया जाएगा।

बयान एनकाउंटर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तीखा जवाब

अगर गोली न चलाएं तो क्या गोली खाए पुलिस

लखनऊ, 3 फरवरी. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित यूपी फार्मा कॉन्क्लेव 1.0 के उद्घाटन के दौरान कानून-व्यवस्था, एनकाउंटर, निवेश और भारत की वैश्विक भूमिका पर खुलकर अपनी बात रखी।

एनकाउंटर को लेकर उठने वाले सवाल पर सीएम योगी ने सख्त लहजे में जवाब देते हुए कहा कि पुलिस को पिस्तौल दी गई है, ताकि वह आत्मरक्षा कर सके. उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की नीति 'जिरो टॉलरेंस' की है, जिसमें अपना-पराया कोई नहीं होता. कार्यक्रम में निवेश, रोजगार



और भू-माफिया पर कार्रवाई के आंकड़े भी साझा किए गए. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी फार्मा कॉन्क्लेव 1.0 के उद्घाटन समारोह में कानून-व्यवस्था को लेकर अपनी सरकार की नीति को दो दृक शब्दों में रखा. एनकाउंटर पर सवाल उठाने वालों को जवाब देते हुए उन्होंने कहा, हमने भी पुलिस

को पिस्तौल दी है. अगर पुलिस गोली न चलाए तो क्या गोली खाए? सीएम योगी ने साफ किया कि कानून को चुनौती देने वालों के लिए सख्त जरूरी है और यह कार्रवाई पूरी तरह कानून के दायरे में होती है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की 'जिरो टॉलरेंस' नीति के तहत अगर कोई अपना भी अपराध करेगा तो उसके खिलाफ वही कानून लागू होगा, जो माफिया और अपराधियों पर होता है. उन्होंने दावा किया कि एक समय उत्तर प्रदेश में अराजकता और असुरक्षा का माहौल था, लेकिन आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है।

योगी ने बताया कि यूपी को अब तक 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं. भू-माफिया का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा 24 घंटे में 65 हजार एकड़ सरकारी जमीन कब्जामुक्त कराई गई, जिससे राज्य का लैंड बैंक मजबूत हुआ. अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर बोलते हुए सीएम ने कहा भारत अब किसी देश के दबाव में नहीं झुकता और नीतियों पर अडिग रहते हुए वैश्विक मंच पर एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में उभर रहा है।

अमेरिका-यूरोप संबंध पहले जैसे नहीं: मर्ज

बर्लिन. जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा है कि अमेरिका और यूरोप के संबंध बदल गये हैं और अब पुरानी स्मृतियां या पुराने दौर की बातें यूरोप के काम नहीं आएंगी. मर्ज ने ड्यूश बोस ग्रुप के एक सालाना कार्यक्रम में कहा कि दुनिया अभी शायद राजनीतिक अनिश्चितता और अस्थिरता के सबसे बड़े दौर से गुजर रही है, निश्चित रूप से यह एक बड़ा मोड़ है. उन्होंने यूरोप से दुनिया में प्रभाव डालने के लिए एकजुट और दृढ़ तरीके से काम करने का आह्वान किया. श्री मर्ज ने कहा कि यूरोप को रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने, आर्थिक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने, ज्यादा तकनीकी स्वतंत्रता हासिल करने अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए।

बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा है: नीतीश

पटना, 3 फरवरी. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पेश बजट को सम्पूर्ण, समावेशी एवं विकास को बढ़ावा देने वाला बताया और कहा कि इसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा है।

मुख्यमंत्री श्री कुमार ने बिहार विधानमंडल में वित्त मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा पेश किये गये वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये आज कहा कि यह विकसित बिहार का संकल्प पूरा करने वाला बजट है. उन्होंने कहा कि न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर आधारित इस बजट में सभी क्षेत्रों तथा किसानों, उद्यमियों, युवाओं एवं महिलाओं सहित समाज के सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है.



यह सम्पूर्ण, समावेशी एवं विकास को बढ़ावा देने वाला बजट है. इस साल बिहार का बजट तीन लाख 47 हजार करोड़ रुपये से अधिक का है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 30 हजार करोड़ रुपये से अधिक है. वित्तीय वर्ष 2026-27 में बिहार की विकास दर 14.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है. मुख्यमंत्री श्री कुमार ने कहा कि यह बजट बिहार सरकार के सात निश्चय-3 के कार्यक्रमों को पूरा करने में काफी मददगार साबित होगा.

उन्होंने कहा कि सरकार ने अगले पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है. राज्य में वित्तीय संसाधनों का उचित प्रबंधन कर युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है. मुख्यमंत्री श्री कुमार ने बताया कि महिला रोजगार योजना के तहत हर घर की एक महिला को रोजगार के लिये दो लाख रुपये की सहायता के लिये भी प्रावधान किया गया है. राज्य में उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है. बजट महिलाओं के सशक्तीकरण के उद्देश्यों को पूरा करेगा.